हिंदी
विवेक
WE WORK FOR A BETTER WORLD
Issue : 22 -28 February 2026

मातृभूमि की अर्चना का सिद्ध मंत्र

सफल व्यवसाय के सपने को हकीकत बनाइए !

पितांबरी® शॉपी फ्रँचायसी के साथ

पितांबरी ब्रांड के साथ काम करने का अवसर

पितांबरी® अभिनव उत्पाद

३५ सालों का गौरवशाली सफर !

ग्राहकों का पसंदीदा भारतीय ब्रांड

व्यवसाय वृद्धी और आर्थिक प्रगती

पितांबरी शॉपी फ्रँचायसी के फायदे

- मर्यादित निवेश में व्यापार और पर्याप्त रिटर्न
- उत्पादों पर अच्छा मार्जिन
- वर्तमान व्यवसाय के साथ अतिरिक्त उत्पन्न
- फ्रँचायसी नवीकरण शुल्क नही

फ्रँचायसी धारक को क्या मिलेगा ?

- शुरुआत में कुछ मुल्य का माल कंपनी की ओर से दिया जाएगा*
- फ्रँचायसी शुल्क पर महिलाओं को विशेष छूट
- प्रॉडक्ट शेल्फ सुविधा उपलब्ध
- प्रसिद्धी सामग्री और बिलिंग सॉफ्टवेअर दिया जाएगा

*नियम और शर्तें लागू

१४०+ फ्रँचायसी धारकों की तरह अपना सफल व्यवसाय शुरु करने के लिए आज ही संपर्क करें !

पितांबरी प्रॉडक्ट्स प्रा. लि.: संपर्क:- सचिन कासले - 9930329664, मनोज विचारे - 8237112426, उमेश जगताप - 7972078591, विजय घुगे - 9545707788 | टोल फ्री: 18001031299 | CIN: U52291MH1989PTC051314

अनुक्रमणिका

गर्व से गाएं वंदे मातरम्	डॉ. लोकेंद्र सिंह	04
वंदे मातरम् गायन को लेकर उठते विरोध के स्वर	राघव कुमार झा	06
वंदे मातरम् समर्थन और विरोध	डॉ. राजेश्वर उनियाल	07
पहली बार होगी डिजिटल जनगणना	अमित त्यागी	10
बांग्लादेश चुनाव: सत्ता, षडयंत्र व जनमत	विप्लव विकास	12
सीमा पर सैन्य अभ्यास	डॉ. ईलेवान ठाकर	14
बजट की दिशा बनाम वोट की राजनीति	ललित गर्ग	17
तकनीक से सुगम होता जीवन	डॉ. रविंद्र सिंह भड़वाल	19
टी-20 विश्व कप में सुपर 8 तक की यात्रा	राजीव रोहित	21
वन ऐप, ऑल सर्विसेज की ओर भारतीय रेल	योगेश कुमार गोयल	24
छोटे बच्चों को धर्म व आस्था से जोड़ें	डॉ. हिमांशु थपलियाल	26
एकादशी उपवास के स्वास्थ्य लाभ	संकलन	27
साइबर धोखाधड़ी होने पर बैंक देगी मुआवजा	संकलन	28
समाचार	हिंदी विवेक	29

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

पंजीयन शुल्क

वार्षिक मूल्य : 500 रुपये, त्रैवार्षिक मूल्य : 1200 रुपये

पंचवार्षिक मूल्य : 1800 रुपये, आजीवन मूल्य : 20,000 रुपये

कार्यालय : प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर-10, सेक्टर-2, श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे, हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई- 400067 फोन नं. : 022-28675299, 022-28678933

गर्व से गाएं वंदे मातरम

गृह मंत्रालय ने 'वंदेमातरम' के सम्मान के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी किया है। जिनमें राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रगीत का गायन होगा, साथ ही सभी 6 छंदों (कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड) का होगा। गायन के दौरान 'सावधान' की मुद्रा में खड़े होने का निर्देश भी दिया गया है।

मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते कभी कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन के मंत्र और राष्ट्रीय गीत 'वंदेमातरम' के सम्मान के साथ समझौता कर लिया था। राष्ट्रगान को जो सम्मान दिया गया, राष्ट्रगीत को उससे वंचित कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 51ए में राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने को मौलिक कर्तव्य के रूप में रेखांकित किया गया है, लेकिन इसमें राष्ट्रगीत के सम्बंध में कोई निर्देश नहीं मिलता है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान के गायन को रोकता है या गा रहे लोगों के बीच अशांति पैदा करता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, किंतु इस अधिनियम में भी राष्ट्रगीत का अपमान करने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रगीत के सम्मान के प्रति यह उदासीनता क्यों रखी गई? इसका उत्तर सब जानते हैं। इसलिए सभी राष्ट्रभक्त देशवासियों के मन में कसक थी कि आखिर वह दिन कब आएगा जब हम अपने राष्ट्रगीत को वह सम्मान देंगे, जिसका वह प्रारम्भ से अधिकारी है। याद रखें कि जिनके मन में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान नहीं था, वे लोग तो पाकिस्तान चले गए थे। आज जिन्हें भारत में रहकर वंदेमातरम गाने और उसके सम्मान में खड़े होने में दिक्कत है, उन्हें अपने बारे में विचार करना चाहिए। भारत में रहना है तो फिर वंदेमातरम तो गाना पड़ेगा।

मोदी सरकार को साधुवाद कि उसने राष्ट्रीय गीत को उसका खोया हुआ स्वाभिमान एवं प्रतिष्ठा लौटाई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 'वंदेमातरम' के गायन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करके अच्छा कदम उठाया है। इस आदेश के अंतर्गत अब जब भी राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान, दोनों एक साथ बजाए जाएंगे तो पहले 'वंदे मातरम'(राष्ट्रगीत) के सभी छह छंद गाए जाएंगे और उसके बाद 'जन-गण-मन' (राष्ट्रगान) होगा। यह बदलाव केवल प्रक्रियात्मक नहीं है बल्कि इसके ऐतिहासिक और संवैधानिक निहितार्थ भी हैं। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि वंदेमातरम का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय स्थान रहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित इस गीत ने क्रांतिकारियों में जो ऊर्जा भरी, वह इतिहास में दर्ज है।

गृह मंत्रालय का नया आदेश अब आधिकारिक कार्यक्रमों में सभी 6 छंदों (कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड) के गायन की व्यवस्था देता है। साथ ही इसके सम्मान में 'सावधान' की मुद्रा में खड़े होने का निर्देश भी दिया गया है। अधिकतर मुसलमान अपनी धार्मिक आस्थाओं का हवाला देकर राष्ट्रगीत की अवमानना करते थे। याद रखें कि यह सोच केवल वंदेमातरम तक नहीं रुकती है अपितु अनेक अवसरों पर राष्ट्रगान का विरोध भी इसी कुतर्क के साथ मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी तत्वों की ओर से किया गया है क्योंकि भारत की वंदना तो राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' में भी है। उसमें भी भारत को भाग्यविधाता माना गया है और उसकी जय-जयकार की गई है। इसलिए जब कोई वंदेमातरम का विरोध करता है, तब उसके पीछे तर्क कम अपितु साम्प्रदायिक एवं विभाजनकारी मानसिकता का प्रभाव अधिक दिखाई

डॉ. लोकेंद्र सिंह

देता है।

वंदेमातरम के गायन एवं उसके प्रति सम्मान प्रकट करने से जो भी मना करता है, भारत के प्रति उसकी निष्ठा पर संदेह होना स्वाभाविक है। इसी देश में ऐसे भी मुसलमान हुए हैं, जिन्होंने रामकथा का गायन भी किया है और वंदेमातरम का जयघोष भी, लेकिन इसके बाद भी उनकी अपनी धार्मिक निष्ठा में कोई कमी नहीं आई। हम सबको याद रखना चाहिए कि अपना विचार एवं सम्प्रदाय, भारत के स्वाभिमान से बढ़कर नहीं हो सकता है। भारत सरकार ने वंदेमातरम के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करते समय संतुलित दृष्टिकोण दिखाया है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में वंदेमातरम के सम्मान से जुड़े दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान नहीं रखा है। इसका संदेश यही है कि लोग मनपूर्वक राष्ट्रगीत का सम्मान करें। राष्ट्रगीत को पूरा सम्मान देने और उसके गायन को व्यवस्थित करने की सरकार की इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाना है। 'वंदे मातरम' और 'जन-गण-मन' दोनों ही हमारी साझा विरासत हैं और इनका सम्मान किसी नियम से अधिक हमारी अंतरात्मा की आवाज होनी चाहिए। यही सरकार और देशभक्त नागरिकों की आकांक्षा है।

राष्ट्रगीत को लेकर सरकार के दिशा-निर्देश

यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगान (जन-गण-मन) और राष्ट्रगीत (वंदे मातरम्) दोनों का गायन होना है तो प्रोटोकॉल के अनुसार 'वंदे मातरम' को पहले गाया/बजाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा।

सरकारी समारोहों में 'वंदे मातरम' का पूरा संस्करण (सभी 6 अंतरे) गाया या बजाया जाएगा। इससे पहले अधिकांश केवल पहले दो अंतरों का ही गायन होता था, लेकिन अब आधिकारिक आयोजनों के लिए पूर्ण संस्करण को अनिवार्य कर दिया गया है।

राष्ट्रगीत के सभी 6 छंदों की कुल अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित है।

जब भी राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण गाया या बजाया जा रहा हो तो उपस्थित सभी लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य है।

अपवाद: यदि यह किसी फिल्म, न्यूज़रील या डॉक्यूमेंट्री के हिस्से के रूप में बज रहा हो तो दर्शकों का खड़ा होना अपेक्षित नहीं है ताकि प्रदर्शन में बाधा न आए।

यदि राष्ट्रगीत को पुलिस या मिलिट्री बैंड द्वारा बजाया जा रहा है तो इसकी शुरुआत से पहले ड्रम रोल होना चाहिए। ●●●

स्वयं के लिए और अपने परिजनों के लिए ग्रंथ का पंजीयन करें

इस ग्रंथ में आप पढ़ेंगे

- संघ में हो रहे अनगिनत सेवा कार्यों का परिणाम क्या है?
- डॉ. हेडगेवार जी से लेकर डॉ. मोहन भागवत जी तक के सभी सरसंघचालकों का दिशादर्शन...
- राजनीति को केंद्र में न रखकर राष्ट्रीयत्व को क्यों केंद्र में रखा?
- भारत के सम्मुख चुनौतियां और संघ कार्य का प्रभाव
- संघ विचारधारा और परिवर्तन

जैसे विविध मौलिक विषय

ग्रंथ का मूल्य ₹700/-

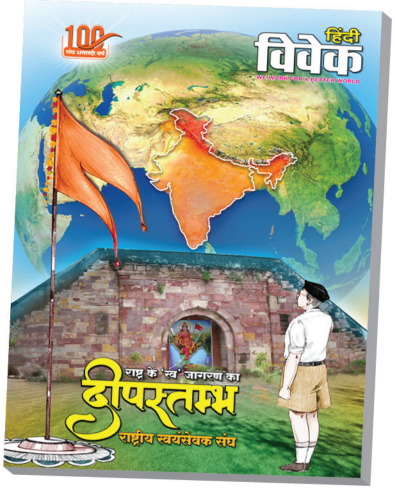

ईमेल – hindivivekvargani@gmail.com

Draft or Cheque should be drawn in the name of HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank Details : State Bank of India, **Branch -** Charkop, A/C No. : 00000043884034193, IFSC Code : SBIN0011694

ग्रंथ पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

सम्पर्क
प्रशांत : 9594961855, संदीप : 9082898483
भोला : 9702203252, कार्यालय : 9594991884

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कॅन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

वंदे मातरम

गायन को लेकर उठते विरोध के स्वर

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को अनिवार्य कर दिया है। जिसको लेकर कई मुस्लिम संगठनों की भृकुटी तन गई और कई विपक्षी पार्टियां भी नाक-भौं सिकोड़ने लगी हैं।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। 28 जनवरी को जारी 10 पृष्ठों के इस आदेश में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 'वंदे मातरम्' का पूरा छह छंदों वाला संस्करण, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है, अब कई महत्वपूर्ण सरकारी और आधिकारिक अवसरों पर अनिवार्य रूप से बजाया या गाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय गीत का गायन मातृभूमि के प्रति सम्मान और शिष्टाचार के साथ किया जाए।

इस दिशा-निर्देश के बाद समाज में इससे सम्बंधित प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इसको लेकर समाज दो हिस्सों में बंट गया है। एक धरा इसको सहज स्वीकार्य करा रहा है तो दूसरा धरा इसका अपना-अपना तर्क देकर विरोध भी कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने वंदे मातरम के सभी छंद गाने का विरोध किया है। संगठन ने कहा कि सरकार का ये आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है। संगठन ने सरकार के आदेश को एकतरफा और मनमाना बताया। जमीयत के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुसलमान किसी को भी वंदे मातरम गाने या बजाने से नहीं रोकते, लेकिन गाने के कुछ छंद मातृभूमि को एक देवता के रूप में दिखाते हैं। ये हमारी मान्यताओं के खिलाफ हैं। मदनी ने यह भी कहा कि एक मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करता है, इसलिए उसे यह गाना गाने के लिए मजबूर करना संविधान के आर्टिकल 25 और सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का साफ उल्लंघन है। इस गाने को जरूरी बनाना और इसे नागरिकों पर थोपने की कोशिश देशभक्ति का इजहार नहीं है बल्कि यह चुनावी राजनीति, एक साम्प्रदायिक एजेंडा और बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है। देश के लिए प्यार का असली पैमाना नारों में नहीं बल्कि किरदार और कुर्बानी में है। इसकी शानदार मिसालें मुसलमानों और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के ऐतिहासिक संघर्ष में खास तौर पर देखी जा सकती हैं। ऐसे फैसले देश की शांति, एकता और डेमोक्रेटिक मूल्यों को कमजोर करते हैं और संविधान के भावना को कमजोर करते हैं। वंदे मातरम को जरूरी बनाना संविधान, धार्मिक आजादी और डेमोक्रेटिक उसूलों पर साफ हमला है।

राघव कुमार झा

वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सरकार का यह निर्णय गैर कानूनी है। धार्मिक आजादी, सेक्युलर मूल्यों के खिलाफ है। सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस ले। वापस नहीं लिया तो पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देगा।

मुस्लिम धर्म के जानकार मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी ने अपना बयान जारी करते हुए वंदे मातरम् की अनिवार्यता पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि हमारे देश में कई धर्म के लोग हैं, जो अपने-अपने धर्म के अनुसार कई खुदा की इबादत करते हैं। कोई एक खुदा को मानता है तो कोई दो, कोई लाखों करोड़ों खुदा को मानता है। इस्लाम केवल एक ही खुदा अल्लाह को मानने की इजाजत देता है।

कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि भाजपा और उसके वैचारिक मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नियमित रूप से इस गीत से बचते हैं। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा, यह बहुत ही विडम्बनापूर्ण है कि जो लोग आज राष्ट्रवाद के संरक्षक होने का दावा करते हैं (आरएसएस और भाजपा) उन्होंने कभी 'वंदे मातरम्' नहीं गाया।

•••

समर्थन और विरोध

प्रतिक्रिया

राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर धार्मिक और राजनीतिक चर्चा चल रही है कि क्या यह सभी भारतीयों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है? भारत के विपक्षी दल व मुस्लिम समाज इसका विरोध किन कारणों से कर रहे हैं, उनके तर्क क्या है और उनके अंदर की छुपी हुई मानसिकता क्या कह रही है? इसका एक संक्षिप्त विश्लेषण यहां प्रस्तुत है।

डॉ. राजेश्वर उनियाल

कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम का सीधा विरोध तो नहीं कर पा रही है, परंतु वंदे मातरम के प्रति कांग्रेस की भावनाएं शुरू से ही अलग-अलग रही है। इस सम्बंध में आदेश जारी किए हैं कि अब सभी सरकारी समारोहों में पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम और फिर उसके बाद राष्ट्रगान जन-गण-मन गाया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी के स्वर बदलते दिखाई दे रहे हैं। उनको चिंता है कि वंदे मातरम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन मिलेगा और दूसरी ओर कांग्रेस के हाथ से मुस्लिम वोट बिखरते चले जाएंगे। इसलिए कांग्रेस की स्थिति 'न तीन में और ना तेरह में' वाली रह गई है। जब नरसिम्हा राव भारत के प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने एक बार इस पर चर्चा करते हुए लोकसभा में कहा भी था कि वंदे मातरम तो हमारे स्वतंत्रता का प्रेरणा सूचक मंत्र रहा है तो फिर हम इसका विरोध कैसे कर सकते हैं?

दूसरी ओर लोकसभा में विपक्ष की दूसरी बड़ी पार्टी समाजवादी दल को इस बात की चिंता है कि अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और समाजवादी पार्टी पीडीए अर्थात पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के दम पर ही चुनाव जीत सकता है। यदि समाजवादी पार्टी ने समय रहते राष्ट्रगीत का प्रबल विरोध नहीं किया तो उनके हाथ से अल्पसंख्यक वोट जो कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20% से अधिक हैं, बिदक सकते हैं। इसीलिए यूपी के पूर्व मुख्य मंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि इसके पीछे राजनीति और आवश्यक मुद्दों से ध्यान भटकाना है, इसके सिवाय कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी के ने संसद में वंदे मातरम का मुखर विरोध किया है।

वंदे मातरम तो बंगाल की धरती से ही निकला हुआ गीत है, इसलिए ममता बनर्जी वंदे मातरम का खुलकर विरोध नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उनका विरोध है कि वंदे

मातरम से मुसलमानों की भावनाएं आहत होंगी, इसलिए इसे अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। वैसे भी पश्चिम बंगाल में शीघ्र ही चुनाव होने वाले हैं।

विपक्षी दलों में सबसे बुरी स्थिति से इस समय वामपंथी दल गुजर रहे हैं। सच्चाई यह है कि ना हीं इनका कोई सम्मानजनक प्रतिनिधित्व संसद में बना हुआ है और न ही केरल के अतिरिक्त किसी राज्य में यह सरकार में है। वास्तव में ये केवल वंदे मातरम का ही विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि ये भारत की प्राचीन संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों पर कुठाराघात करते रहे हैं।

इसी तरह पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माना जाता है। जब भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो उस समय सन 1906 में बिपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम दैनिक समाचार पत्र प्रारम्भ किया था, लेकिन बदलते स्वरूप में अब क्योंकि भारतीय पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण वर्ग एक तरह से वामपंथी विचारधारा वाले तत्वों के आसपास ही समाया हुआ है, इसलिए वे मुस्लिम तुष्टिकरण को बढ़ावा देते हुए वंदे मातरम के प्रति दुर्भावना फैला रहे हैं। विपक्षी दलों व वामपंथी मीडिया के साथ ही हिंदुओं का एक दोगला वर्ग भी है, जिसे सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। इसे हम अति बुद्धिजीवी भी कह सकते हैं। यह वर्ग भी वंदे मातरम के विषय पर केवल अपना अस्तित्व बचाने के लिए अर्थहीन कुतर्क गढ़ता रहता है। जहां तक भारतीय मुस्लिम समाज का सम्बंध है तो वह भी वंदे मातरम के मामले में तीन ओर से घिरा हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदी ही नहीं बल्कि लाहौर से उर्दू में भी वंदे मातरम नामक पत्रिका प्रकाशित होती रही। मुसलमान भी हिंदुओं के साथ वंदे मातरम का जयघोष करते हुए स्वतंत्रता का नारा लगाते थे। उस समय वंदे मातरम किसी धर्म या संस्कृति का प्रतीक ना होकर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से भगाने का महत्वपूर्ण सूत्र था, किंतु मुस्लिम लीग की स्थापना और भारत का विभाजन कर अलग मुस्लिम देश बनाने के लिए मुसलमानों को धर्म के नाम पर भड़काना आवश्यक था। इसके लिए मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध करना प्रारम्भ किया। आज भी कट्टर मुसलमानों के मौलानाओं का एक वर्ग ऐसा है जो कि वंदे मातरम का खुलकर विरोध कर रहे हैं। विशेषकर यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास 'आनंद मठ' से लिया गया है, जिसमें मुसलमानों को देश का शत्रु बताया गया है, जिससे मुस्लिम लीग को आपत्ति थी। वरिष्ठ इस्लामी विद्वान और दारुल उलूम देवबंद के वर्तमान प्रमुख मौलाना अरशद मदानी ने स्पष्ट किया है कि हालांकि मुसलमानों को दूसरों द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पाठ करने या गाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे धार्मिक मान्यताओं के कारण इसमें भाग नहीं ले सकते। इसके साथ ही एआईएमपीएलबी ने इस निर्णय को संवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बताते हुए सरकार से अधिसूचना को तत्काल वापस लेने की मांग की है, अन्यथा वह इसे न्यायालय में चुनौती देंगे। मुसलमानों के प्रमुख संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद के दोनों गुटों ने भी सरकार के इस आदेश पर आपत्ति जताई है, लेकिन वही दूसरी ओर मुसलमानों के बहुत बड़े वर्ग को वंदे मातरम से कोई भी संशय नहीं है। यह बात सही है कि मुस्लिम धर्म और कुरान एक ईश्वर की बात करता है। इसलिए वह अल्लाह के अतिरिक्त किसी को भी पूजनीय स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन जब हम राष्ट्रीय महत्व और प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं तो वह धर्म से बहुत ऊंचा होता है। इसलिए राष्ट्रवादी मुसलमान जोर-शोर से वंदे मातरम का गायन कर रहे हैं। इसी के साथ जो मुस्लिम समाज शिक्षित है, जो छात्र उच्चस्तरीय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वह इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि यदि आप किसी राष्ट्र के नागरिक हैं तो उस राष्ट्र के नियमों, परम्पराओं और संविधान का सम्मान करना उनका कर्तव्य होता है। हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, वामपंथी मीडिया व ढोंगी सेकुलर आदि सहित कई मुस्लिम दल सरकार से वंदे मातरम के सभी छह श्लोकों का पाठ अनिवार्य करने के कदम का विरोध कर रहे हैं। ●●●

Vipin Aggarwal
THE SAFFRON EXPERT ™

केसर तिलक-एक अज्ञात रहस्य

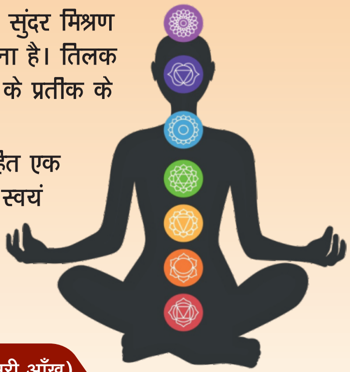

केसर तिलक

केसर तिलक आध्यात्मिकता, परम्परा और स्वास्थ्य का एक सुंदर मिश्रण है। यह शुद्ध और पवित्र गंगाजल के साथ शुद्ध केसर से बना है। तिलक आंतरिंत ऊर्जा को जाग्रत करने, मन की रक्षा करने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और आध्यात्मिक के प्रतीक के रूप में लगाया जाता है।

माथे, गले और नाभि पर केसर तिलक लगाना आयुर्वेद और आध्यात्मिक परम्पराओं में निहित एक प्राचीन प्रथा है। प्रत्येक बिंदू को शरीर में एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र माना जाता है और केसर स्वयं औषधीय और आध्यात्मिक महत्व रखता है। प्रत्येक क्षेत्र के लाभ इस प्रकार हैं–

केसर तिलक के अद्भुत लाभ

1. माथा आज्ञा चक्र (तीसरी आँख)
- अंतर्ज्ञान, एकाग्रता और बुद्धि का केंद्र
- ऊर्जा को संतुलित करता है और ध्यान शक्ति बढ़ाता है

2. कान
- सतर्कता, जागरुकता और ग्रहणशीलता का प्रतीक
- कानों के पास केसर तिलक लगाने से श्रवण-एकाग्रता और संतुलन बढ़ता है

3. कंठ-विशुद्धि चक्र
- संवाद कौशल्य, आत्मविश्वास और स्व-अभिव्यक्ति को बढ़ाता है
- स्पष्ट संवाद, आंतरिक सत्य और आत्मविश्वास को सशक्त करता है

4. नाभि
- नाभि को शरीर का ऊर्जा केंद्र माना जाता है
- यहाँ केसर तिलक लगाने से शरीर को पोषिण मिलता है, पचनशक्ति बढ़ाता है और आंतरिक अंगों की रक्षा होती है

ज्योतिष के अनुसार, केसर तिलक बृहस्पति (ज्ञान, धन, आध्यात्मिकता), बुध (बुद्धि, वित्त, संचार), केतु (बोध, अंतर्ज्ञान, शांति) और मंगल (साहस, शक्ति) की ऊर्जा को संतुलित करता है। प्रसिद्ध लाल किताब में केसर और केसर तिलक से संबंधित अनेक उपाय बताए गए हैं।

लगातार तीन से छह महीनों तक केसर तिलक लगाने से जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं और यह समृद्धि की सिद्ध कुंजी है। केसर तिलक से अपने दिन की शुरुआत करें।

GROCERIES IMPEX : +91-9999092561, 9650635204 | vipin@groceriesimpex.com
Registered Office Address : R-49, Rita Block, Shakarpur, Delhi-110092.
Packing Unit : D-94/A, Matiala Extension, Dwarka, New Delhi-110059.

पहली बार होगी डिजिटल जनगणना

भारत की पहली डिजिटल जनगणना देश के इतिहास में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। यह न केवल प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगी बल्कि नागरिकों की भागीदारी और डेटा की विश्वसनीयता को भी सुदृढ़ करेगी।

अमित त्यागी

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जनगणना केवल जनसंख्या गिनने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक छवि प्रस्तुत करने का सबसे बड़ा माध्यम है। प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित होने वाली जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं और संसाधनों के वितरण की आधारशिला होती है। अब भारत अपनी पहली डिजिटल जनगणना की ओर बढ़ रहा है, जो पारम्परिक कागजी प्रक्रिया से हटकर तकनीक आधारित प्रणाली को अपनाने का महत्वपूर्ण कदम है। यह परिवर्तन न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएगा बल्कि डेटा की गुणवत्ता और पारदर्शिता को भी सुदृढ़ करेगा। डिजिटल जनगणना 01 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 है। जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश जैसे बर्फीले क्षेत्रों में संदर्भ तिथि 1 अक्टूम्बर, 2026 रहेगी। संदर्भ तिथि से तात्पर्य है कि इस समय से पूर्व जन्मे व्यक्ति ही जनगणना में शामिल किए जाएंगे। भारत की पिछली जनगणना 2011 में संदर्भ तिथि मार्च 2011 के पहले दिन 00:00 बजे तथा जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के बर्फ से ढके क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि अक्टूम्बर, 2010 के पहले दिन 00.00 बजे थी।

जनगणना दो चरणों में पूर्ण होगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस का है जिसमें आवासीय स्वरूप, दीवार, फर्श, छत, शौचालय एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी होगी। दूसरा चरण जनसंख्या की गणना का है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, जैसे- आयु, शिक्षा, रोजगार एवं जाति शामिल है।

डिजिटल जनगणना की आवश्यकता

पिछली जनगणनाओं में गणनाकर्मी घर-घर जाकर कागजी फॉर्म भरते थे। इस प्रक्रिया में समय अधिक लगता था और डेटा को संकलित करने, सुरक्षित रखने तथा विश्लेषण करने में भी कठिनाई होती थी। कभी-कभी मानवीय त्रुटियां, डेटा की पुनरावृत्ति या देरी जैसी समस्याएं सामने आती थीं। डिजिटल जनगणना इन चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करती है। टैबलेट, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डेटा सीधे डिजिटल रूप में दर्ज किया जाएगा, जिससे जानकारी तुरंत केंद्रीय सर्वर तक पहुंच सकेगी।

डिजिटल जनगणना के अंतर्गत गणनाकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे टैबलेट या स्मार्टफोन आधारित एप्लिकेशन का सही उपयोग कर सकें। नागरिकों को भी स्वयं-गणना की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे निर्धारित

पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों और तकनीक से परिचित लोगों के लिए उपयोगी होगी। इस प्रक्रिया में जीआईएस तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे प्रत्येक घर का सटीक भौगोलिक स्थान दर्ज हो सकेगा। इससे नक्शों के आधार पर जनसंख्या का विश्लेषण और योजना निर्माण अधिक सटीक ढंग से किया जा सकेगा। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से डेटा की त्वरित जांच सम्भव होगी, जिससे गलत या अधूरी प्रविष्टियों को तुरंत सुधारा जा सकेगा। डिजिटल जनगणना के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। पहला, यह समय और संसाधनों की बचत करेगी। कागज, छपाई और परिवहन पर होने वाला खर्च कम होगा। दूसरा, डेटा की शुद्धता बढ़ेगी क्योंकि त्रुटियों की सम्भावना कम होगी। तीसरा, आंकड़ों का विश्लेषण तेजी से किया जा सकेगा, जिससे सरकार को नीतियां बनाने में कम समय लगेगा। इसके अतिरिक्त डिजिटल डेटा को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सकेगा। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास से सम्बंधित योजनाओं में जनगणना के आंकड़ों का सीधा उपयोग किया जा सकेगा। इससे लक्षित लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी।

चुनौतियां और सावधानियां

हालांकि डिजिटल जनगणना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या हो सकती है। इसके लिए ऑफलाइन डेटा संग्रह की सुविधा रखी जाएगी, जिसे बाद में अपलोड किया जा सकेगा।

डेटा सुरक्षा और गोपनीयता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी होगी। मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय, एन्क्रिप्शन और सुरक्षित सर्वर का उपयोग अनिवार्य होगा ताकि किसी भी प्रकार की डेटा चोरी या दुरुपयोग को रोका जा सके।

डिजिटल जनगणना प्रशासनिक प्रणाली को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाएगी। इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बेहतर होगा। नीति-निर्माण में सटीक आंकड़ों का उपयोग होगा, जिससे योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ेगी। सामाजिक दृष्टि से भी यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। डिजिटल प्रक्रिया से नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी। स्वयं-गणना की सुविधा से लोगों में जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। यह डिजिटल साक्षरता को भी प्रोत्साहित करेगा और देश को डिजिटल भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाएगा। ●●●

राष्ट्रीय भावनाओं को जाग्रत करनेवाली सामाजिक व पारिवारिक पत्रिका

हिंदी विवेक
We Work For A Better World
मासिक पत्रिका

शुल्क ₹ 500

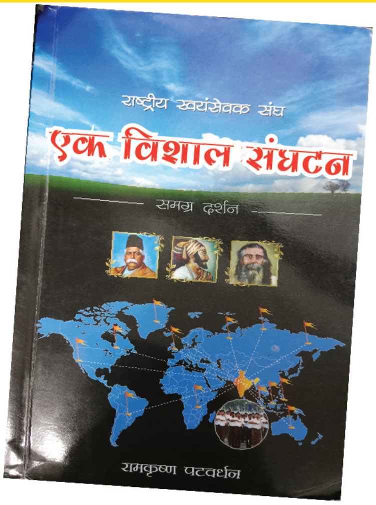

रा. स्व. संघ की स्थापना से लेकर शतकपूर्ति की यात्रा के विभिन्न पड़ावों तथा भविष्य के उद्देश्यों का सम्पूर्ण संकलन व आंकलन करने वाली पुस्तक

ऑनलाईन पंजीयन करने के बाद कृपया 9594991884 पर कॉल करके सूचित करें या व्हाट्सअप करें।

Draft or Cheque should be drawn in the name of : **HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA-HINDI VIVEK**

Bank : Bank of Maharashtra **Branch :** Prabhadevi

A/C No. : 60085108000 **IFSC :** MAHB0000318

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कॅन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

सम्पर्क - 9594991884 **Email : hindivivekvargani@gmail.com**

फरवरी 2026 में नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ बांग्लादेश ने एक नया अध्याय प्रारम्भ किया है। निर्वाचित सरकार का होना निश्चित रूप से अंतरिम या कथित बाहरी प्रभाव वाली व्यवस्था से बेहतर है, परंतु लोकतंत्र की सच्ची परीक्षा आने वाले वर्षों में होगी।

विप्लव विकास

बांग्लादेश चुनाव: सत्ता, षडयंत्र व जनमत

दिसम्बर 2025 से फरवरी 2026 के बीच बांग्लादेश ने जिस राजनीतिक संक्रमण का अनुभव किया, वह केवल एक चुनावी प्रक्रिया नहीं थी बल्कि वैधता, स्थिरता और राष्ट्रीय आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना की खोज भी थी। पिछले 2 वर्षों में बांग्लादेश ने असाधारण राजनीतिक उथल-पुथल और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अमानवीय अत्याचार देखा। 15 वर्षों से अधिक समय तक सत्ता में रही शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग के शासन ने एक ओर तीव्र आधारभूत ढांचा विकास, ऊर्जा परियोजनाएं और सामाजिक सूचकांकों में सुधार दर्ज किया तो दूसरी ओर राजनीतिक केंद्रीकरण, विपक्ष पर दबाव और चुनावी पारदर्शिता को लेकर गम्भीर आरोपों का सामना भी किया। 2024 में व्यापक विरोध प्रदर्शनों, प्रशासनिक अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच सत्ता परिवर्तन हुआ। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, वैश्विक शक्तियों की आर्थिक-रणनीतिक दिलचस्पी और मानवाधिकार विमर्श के अंतरराष्ट्रीयकरण ने इस संदेह को हवा दी कि सत्ता परिवर्तन में विदेशी शक्तियों की भूमिका से नकारा नहीं किया जा सकता। शेख हसीना की सरकार को केवल घरेलू असंतोष ने नहीं हटाया बल्कि अंतरराष्ट्रीय शक्ति-संतुलन ने भी इसमें योगदान दिया था।

सत्ता परिवर्तन के बाद बनी अंतरिम व्यवस्था, जिसमें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनूस की प्रमुख भूमिका रही, देश के भीतर चर्चा का विषय बन गई। आलोचकों ने इसे पूर्ण जनादेश से रहित और बाहरी समर्थन पर आधारित प्रशासन बताया, जबकि उनके समर्थकों ने इसे लोकतांत्रिक पुनर्गठन का आवश्यक चरण कहा, परंतु आम जनता के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि क्या यह व्यवस्था उन्हें आर्थिक राहत, सामाजिक स्थिरता और राजनीतिक विश्वास दे सकेगी। महंगाई, रोजगार संकट और निवेश में सुस्ती ने जनजीवन को प्रभावित किया था। युवा जनसंख्या, जो बांग्लादेश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है, भविष्य को लेकर आशंकित थी। हिंदुओं और अन्यान्य अल्पसंख्यकों पर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता यूनूस के शासन में अमानवीय अत्याचार हुए और इसने ये प्रश्न पूरी दुनिया के समक्ष उठाया कि क्या नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद यूनूस बांग्लादेश में तालिबानी शासन नहीं चला रहे थे? क्या उनके शासन में काफिरों की हत्या जिहादियों का अधिकार नहीं बन गया था? क्या उन्हें जो शांति पुरस्कार दिया गया था, उन्होंने अपने 'आका' की जी-हुजूरी में अपने कठपुतली सरकार में उसकी कीमत नहीं चुकाई? इतिहास इस निर्मम सत्य पर जब विचार करेगा तो ये बौद्धिक वर्ग कौन सा मुंह दिखाएगा? अस्तु, इसी पृष्ठभूमि में 11 दिसम्बर 2025 में आम चुनाव की घोषणा

हुई और 12 फरवरी 2026 को मतदान सम्पन्न हुआ।

चुनाव अभियान के दौरान जनता के मन में एक स्पष्ट आकांक्षा उभरकर सामने आई, उन्हें एक ऐसी स्थिर, निर्वाचित और जवाबदेह सरकार चाहिए थी जो बुनियादी सुविधाओं की गारंटी दे सके और देश को अनिश्चितता के दौर से बाहर निकाल सके। विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इस भावना को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त किया। चुनाव परिणामों में बीएनपी को स्पष्ट बहुमत मिला और 17 फरवरी 2026 को उसके नेता तारिक रहमान ने प्रधान मंत्री पद की शपथ लीं। यह क्षण प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह अंतरिम या कठपुतली शासन से निकलकर प्रत्यक्ष जनादेश पर आधारित सरकार की वापसी का संकेत देता था। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए बनी सरकार किसी भी अस्थायी या विवादित संरचना से अधिक वैधता रखती है, इसमें कदाचित् ही कोई संदेह हो।

फिर भी हमें यह स्पष्ट स्वीकार करना आवश्यक है कि नई सरकार के बारे में अंतिम निर्णय देना अभी जल्दबाजी होगी। जनादेश मिलना एक बात है, परंतु सुशासन स्थापित करना दूसरी। आर्थिक पुनरुद्धार, संस्थागत सुधार, न्यायिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक हिंदुओं, बौद्धों के योगक्षेम की सुरक्षा तथा संतुलित विदेश नीति, विशेषकर भारत, चीन, पाकिस्तान और पश्चिमी देशों के साथ, नई सरकार की कसौटी बनेंगे। यदि यह प्रशासन राजनीतिक प्रतिशोध से ऊपर उठकर समावेशी विकास और पारदर्शिता को प्राथमिकता देता है तो 2026 का यह चुनाव बांग्लादेश के लोकतांत्रिक इतिहास में निर्णायक मोड़ सिद्ध हो सकता है, लेकिन यदि सत्ता पुनः केंद्रीकरण और ध्रुवीकरण की ओर बढ़ती है तो अस्थिरता का चक्र फिर लौट सकता है।

जनता ने पूर्व कठपुतली अंतरिम सरकार को पूर्णतः नकारा, इसका कारण केवल राजनीतिक विरोध नहीं था। यह थकान, अविश्वास और अनिश्चितता का संचयी परिणाम था। जब नागरिकों को यह लगे कि उनकी राजनीतिक भागीदारी सीमित हो रही है या सत्ता संरचना अपरिवर्तनीय हो गई है तो परिवर्तन की मांग स्वाभाविक हो जाती है। बांग्लादेश की जनता ने अपने मत के माध्यम से यह संदेश दिया कि वे स्थिरता चाहती है, परंतु वह स्थिरता लोकतांत्रिक वैधता पर आधारित होनी चाहिए। इतना स्पष्ट है कि 2026 का जनादेश केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि राजनीतिक परिपक्वता की अभिव्यक्ति है और अब जिम्मेदारी नई सरकार की है कि वह इस विश्वास को परिणामों में बदलकर दिखाए।

•••

आपकी आवाज को बुलंद करने वाली

सम्पूर्ण पारिवारिक व सामाजिक मासिक पत्रिका

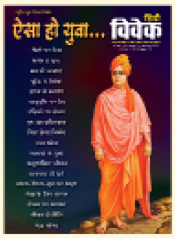
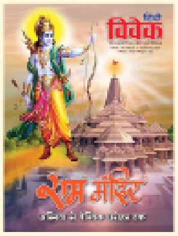

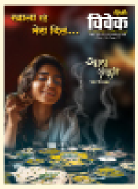

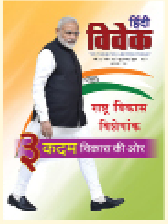

हिंदी विवेक

" We Work For A Better World"

सदस्यता शुल्क

- वार्षिक मूल्य : रु. 500/-
- त्रैवार्षिक मूल्य : रु. 1,200/-
- पंचवार्षिक मूल्य : रु. 1,800/-
- संरक्षक मूल्य : रु. 20,000/-
- विदेशी सदस्यता शुल्क वार्षिक : रु. 5,000/-

खुद ग्राहक बनें व बनाएं

- जन्म दिन तथा अन्य समारोहों में हिंदी विवेक उपहार के रूप में भेंट करें।
- मित्रों, रिश्तेदारों तथा शुभचिंतकों को हिंदी विवेक की सदस्यता प्रदान करें।
- अपने दिवंगत स्नेहीजनों की स्मृति में 11, 21, 51 या 101 पाठकों को सदस्यता दें।
- विवाह के अवसर पर सदस्यता उपहार में दें।
- नववर्ष की शुभकामना के रूप में ग्रीटिंग कार्ड के स्थान पर हिंदी विवेक का सदस्यता रसीद प्रदान करें।

हिंदी विवेक कार्यालय

प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर 10, सेक्टर - 2, श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे, हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई - 400067

सम्पर्क : +91 95949 91884

hindivivekvargani@gmail.com / hindivivekadvt@gmail.com

युद्धाभ्यास

पाकिस्तानी सीमा पर वायु शक्ति अभ्यास और भारत-अमेरिका के बीच होनेवाले संयुक्त सैन्य अभ्यास 'वज्र प्रहार' से ये स्पष्ट हो जाएगा कि बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क और तैयार है।

डॉ. ईलेवान ठाकर

वज्र प्रहार और वायु शक्ति सैन्य अभ्यास

भारत-अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार (23 फरवरी से 16 मार्च) और 27 फरवरी को पाकिस्तान सीमा के पास आयोजित होने वाले वायु शक्ति अभ्यास से न केवल सैन्य तैयारियों को नई धार देगी बल्कि कूटनीतिक, तकनीकी और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी स्पष्ट संदेश मिलेगा। इन अभ्यासों ने यह दिखाया जाएगा कि आधुनिक दौर में सैन्य अभ्यास केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, अंतरराष्ट्रीय सम्बंध और सामरिक संतुलन के अहम हथियार भी बन जाएंगे। आज का सुरक्षा वातावरण बहुआयामी हो चुका है। पारम्परिक युद्ध के साथ-साथ आतंकवाद, साइबर हमले, ड्रोन तकनीक, मिसाइल क्षमता और सूचना युद्ध जैसी चुनौतियां सामने हैं। ऐसे में सैन्य अभ्यासों का महत्व और बढ़ गया है। सीमा क्षेत्रों में आयोजित अभ्यास सैनिकों को वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों का अनुभव कराते हैं, जिससे वे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और सटीक निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास दोनों देशों की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक माना जा रहा है। यह अभ्यास विशेष रूप से स्पेशल फोर्सेज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने पर केंद्रित रहा। इस अभ्यास के अंतर्गत आतंकवाद-रोधी अभियानों का संयुक्त प्रशिक्षण, पर्वतीय और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में युद्ध कौशल, आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रयोग और खुफिया जानकारी साझा करने की प्रक्रियाओं को परखा गया। दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे की युद्ध-नीति, संचालन पद्धति और तकनीकी क्षमताओं को समीप से समझने का अवसर मिला।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वज्र प्रहार जैसे अभ्यास केवल सैन्य स्तर पर ही नहीं बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण हैं। यह अभ्यास वैश्विक मंच पर यह संदेश देता है कि भारत और अमेरिका सुरक्षा, स्थिरता और आतंकवाद के विरुद्ध साझा दृष्टिकोण रखते हैं। इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी मजबूती मिलती है। 27 फरवरी को पाकिस्तान सीमा के पास आयोजित वायु शक्ति अभ्यास का उद्देश्य वायुसेना की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और सटीक प्रहार की दक्षता को परखना है। इस अभ्यास में फाइटर जेट्स की संयुक्त उड़ान, एयर-डिफेंस सिस्टम का परीक्षण, रडार नेटवर्क की प्रभावशीलता और ग्राउंड फोर्स के साथ समन्वय को परखा जाएगा। इनमें विशेष बात यह होगी कि यह अभ्यास दिन-रात और प्रत्येक मौसम में ऑपरेशन की तैयारी पर केंद्रित रहने में सक्षम रहेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में वायुसेना तुरंत और प्रभावी कार्रवाई कर सके। सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह के अभ्यास सुरक्षा कवच को मजबूत करते हैं और सम्भावित खतरों को पहले

ही निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ाते हैं।

सैन्य अभ्यास बहु-स्तरीय उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ये युद्ध-तैयारी और कौशल-विकास का माध्यम होते हैं। सैनिकों को दबाव में निर्णय लेने, सीमित समय में कार्रवाई करने और जटिल परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण मिलता है। अभ्यासों के दौरान नई तकनीकों, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। इससे तकनीकी कमियों की पहचान होती है और उन्हें समय रहते सुधारा जा सकता है। बड़े पैमाने पर होने वाले सैन्य अभ्यास सम्भावित विरोधियों को यह संदेश देते हैं कि देश पूरी तरह तैयार है और किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। सैन्य अभ्यासों का सीधा प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। नियमित अभ्यासों से सीमाओं पर घुसपैठ, आतंकवादी गतिविधियों और पारम्परिक युद्ध के जोखिम कम होते हैं। इसके साथ ही ये अभ्यास कूटनीतिक स्तर पर भी अहम भूमिका निभाते हैं। मित्र देशों के साथ संयुक्त अभ्यास रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हैं और वैश्विक मंच पर देश की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में विश्वास बढ़ता है और क्षेत्रीय स्थिरता को बल मिलता है। सैन्य अभ्यासों का एक महत्वपूर्ण पहलू सैनिकों का मनोबल है। यथार्थपरक प्रशिक्षण से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे संकट की घड़ी में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर पाते हैं। इसका अप्रत्यक्ष लाभ नागरिकों को भी मिलता है। जब सुरक्षा बल मजबूत और तैयार होते हैं तो आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ती है। आपात स्थितियों में त्वरित राहत और प्रभावी प्रतिक्रिया सम्भव हो पाती है। सीमा पर होने वाले सैन्य अभ्यास इसलिए कारगर माने जाते हैं क्योंकि वे वास्तविक परिस्थितियों का अनुकरण करते हैं। भौगोलिक, मौसमीय और रणनीतिक चुनौतियों का अनुभव सैनिकों को इन्हीं अभ्यासों से मिलता है। आधुनिक युद्ध अब केवल थल, जल और वायु तक सीमित नहीं है। साइबर, अंतरिक्ष और सूचना युद्ध भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। सैन्य अभ्यास इन सभी आयामों को समाहित करते हैं। थल, जल और वायु सेनाओं के संयुक्त अभ्यास से नेटवर्क-सेंट्रिक वॉरफेयर की क्षमता विकसित होती है, जिससे त्वरित निर्णय और लचीलापन मिलता है। अभ्यास के दौरान अप्रत्याशित परिदृश्य तैयार किए जाते हैं, जिससे नेतृत्व और सैनिकों में संकट प्रबंधन की क्षमता विकसित होती है। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में ऐसे अभ्यास अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन गए हैं।

●●●

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए मौलिक एवं संग्रहणीय पुस्तक

हिंदी विवेक
" We Work For A Better World"

पद्मश्री रमेश पतंगे लिखित
'हिंदी विवेक' द्वारा प्रकाशित

हम संघ में क्यों हैं...

संघ विचारों की मूल प्रेरणा, संघकार्य को समझने की प्रक्रिया और इन सभी से संघ स्वयंसेवकों को अनायास मिलनेवाले राष्ट्रबोध और कर्तव्यबोध का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है।

पंजीयन करें

पुस्तक का मूल्य ₹250/-

Draft or Cheque should be drawn in the name of **HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK**

Bank Details : State Bank of India, **Branch -** Charkop, A/C No. : 00000043884034193, IFSC Code : SBIN0011694

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कॅन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ग्रंथ पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

प्रशांत : 9594961855, संदीप : 9082898483, भोला : 9702203252, कार्यालय : 9594991884

50+ YEARS OF MOMENTUM
अर्थ सहकारेण कल्याणम्
दि कल्याण जनता सहकारी बँक लि.
मल्टी-स्टेट शेड्युल्ड बँक
सोने तारण कर्ज
जलद कर्ज
कमी प्रक्रिया शुल्क
व्याजदर
९.५०%* वार्षिक
* अटी व शर्ती लागू
TOLL FREE: 1800 233 1919
kalyanjanata.in
KJSBank

दृष्टिकोण

बजट की दिशा बनाम वोट की राजनीति

ललित गर्ग

बजट केवल आय-व्यय के कागजात नहीं होते बल्कि शासन की वैचारिक दिशा का दर्पण होता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने विकास, निवेश और रोजगार को केंद्रीय धुरी बनाकर बजट को भविष्य की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया है, वहीं पश्चिम बंगाल के लिए भी यह आत्ममंथन का अवसर है।

वित्त वर्ष 2026-27 के प्रांतीय बजटों ने भारतीय संघीय ढांचे की विविध आर्थिक सोच को एक साथ सामने रख दिया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल- तीनों राज्यों ने अपने-अपने राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों में बजट प्रस्तुत किए, परंतु इनके दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। कहीं दीर्घकालिक विकास और रोजगार सृजन की ठोस आधारशिला रखने का प्रयास है, तो कहीं चुनावी वर्ष की आहट के बीच तात्कालिक लोकलुभावन घोषणाओं की भरमार। यही अंतर स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा और राजनीतिक स्वार्थ के बीच की रेखा को रेखांकित करता है।

उत्तर प्रदेश का बजट एक स्पष्ट संदेश देता है- मुफ्तखोरी नहीं, अवसर, उपभोग नहीं-उत्पादन, निर्भरता नहीं- आत्मनिर्भरता। मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट में अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो 13 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि राज्य को रोजगार का पावरहाउस बनाने की रणनीति का हिस्सा है। औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और डेटा सेंटरों के विकास के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के बजट में 76

प्रतिशत की वृद्धि कर 2,059 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा 'उत्तर प्रदेश एआई मिशन' के लिए 225 करोड़ रुपए की घोषणा यह दर्शाती है कि राज्य डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर निर्णायक कदम बढ़ा रहा है। पांच गीगावॉट क्षमता के डेटा सेंटर क्लस्टर उच्च कौशल आधारित नौकरियों के द्वार खोलेंगे। यह दृष्टि निर्माण से संचालन तक की पूरी श्रृंखला को जोड़ती है, जिसमें श्रमिक से लेकर इंजीनियर और सप्लाई चेन प्रबंधक तक सभी के लिए अवसर हैं।

राजस्थान का बजट भी आधारभूत ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवा सशक्तिकरण पर केंद्रित दिखाई देता है। उप मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 21.52 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान स्टेट टेस्ट एजेंसी की स्थापना, 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा, 1000 स्कूलों में एआई लैब की स्थापना और मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता जैसी घोषणाएं स्पष्ट करती हैं कि सरकार भविष्य की पीढ़ी को प्रतिस्पर्धी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना चाहती है। स्वास्थ्य ढांचे के सुदृढ़ीकरण, ट्रॉमा सेंटरों के लिए 150 करोड़ रुपए, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व रिकॉर्ड सुधार जैसे कदम सामाजिक-आर्थिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में हैं। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी योजना का विस्तार और पूर्व सैनिकों के लिए प्रशिक्षण प्रावधान यह दर्शाते हैं कि बजट में सामाजिक समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण दोनों का संतुलन साधने का प्रयास है।

इसके विपरीत पश्चिम बंगाल का अंतरिम बजट चुनावी वर्ष की राजनीति से अधिक प्रभावित प्रतीत होता है। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा प्रस्तुत 4.06 लाख करोड़ रुपए के बजट में 'लक्ष्मी भंडार' योजना के अंतर्गत महिलाओं को अतिरिक्त 500 रुपए प्रतिमाह देने और 'बांग्ला युवा साथी' योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह भत्ता देने की घोषणा प्रमुख रही। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत वृद्धि और आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी निश्चित रूप से राहतकारी कदम हैं, किंतु मात्र अल्पसंख्यक मामलों के लिए 5700 करोड़ से अधिक की इतनी बड़ी धनराशि देना मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति नहीं तो क्या है? प्रश्न यह है कि क्या यह दीर्घकालिक विकास की ठोस रणनीति है? जब राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचे की चुनौतियां गम्भीर हों, तब मात्र प्रत्यक्ष नकद सहायता योजनाओं पर बल देना क्या आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से उचित है?

लोकतंत्र में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आवश्यक हैं, परंतु उनका स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करे, न कि स्थायी निर्भरता को। उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने जहां औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा सुधार और स्वास्थ्य ढांचे को प्राथमिकता देकर उत्पादन और रोजगार आधारित अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करने का प्रयास किया है, वहीं पश्चिम बंगाल का बजट चुनावी मानस को साधने की दिशा में अधिक केंद्रित प्रतीत होता है। विशेष रूप से जब बजट में अल्पसंख्यक वर्गों को लक्षित कर प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं का विस्तार किया जाता है और आधारभूत संरचनात्मक सुधारों की चर्चा अपेक्षाकृत सीमित रहती है, तब यह आशंका स्वाभाविक है कि कहीं यह वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा तो नहीं।

स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा का अर्थ है- पारदर्शिता, दीर्घकालिक सोच और समान अवसर। यदि बजट का उद्देश्य केवल चुनाव पूर्व संतुष्टि प्रदान करना रह जाए तो वह वित्तीय अनुशासन और विकास की निरंतरता को कमजोर कर सकता है। इसके विपरीत जब बजट आधारभूत ढांचे, कौशल विकास, उद्योग और डिजिटल नवाचार पर केंद्रित होता है, तब वह आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थाई समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। उत्तर प्रदेश का लॉजिस्टिक्स हब मॉडल, डेटा सेंटर क्लस्टर और औद्योगिक विस्तार हो या राजस्थान का शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे का उन्नयन- ये कदम अल्पकालिक लोकप्रियता से अधिक दीर्घकालिक लाभ पर केंद्रित हैं।

यह भी विचारणीय है कि चुनावी वर्ष में प्रस्तुत अंतरिम बजट का दायरा सीमित होता है, परंतु उसकी प्राथमिकताएं राज्य की आर्थिक दिशा को संकेतित करती हैं। यदि प्राथमिकता प्रत्यक्ष नकद अंतरण और सीमित वर्गों को लक्षित रियायतों तक सिमट जाए तो व्यापक आर्थिक ढांचा पिछड़ सकता है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में यही चिंता उभरती है कि क्या राज्य ने औद्योगिक पुनरुत्थान, निवेश आकर्षण और कौशल उन्नयन के लिए उतनी ही आक्रामक योजना बनाई है, जितनी प्रत्यक्ष सहायता योजनाओं के लिए?

●●●

विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। यह हमारे दैनिक जीवन की हर सुविधा, हर समाधान और हर प्रगति में समाहित है। एआई इम्पैक्ट समिट में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सम्बोधन में तकनीकी को लेकर भारत की इस प्रतिबद्धता को जोर देकर दोहराया है।

डॉ. रविंद्र सिंह भड़वाल

तकनीक से सुगम होता जीवन

प्रत्येक युग में तकनीक ने मनुष्य के श्रम को कम किया, समय की बचत की और जीवन को अधिक सुगम-व्यवस्थित बनाया है। आज हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां मशीनें केवल आदेश का पालन ही नहीं कर रहीं बल्कि अपने अपार डाटा संग्रह और पूर्व के दिशा-निर्देशों के आधार पर सीख और निर्णय भी ले रही हैं। ऐसे समय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (28 फरवरी) हमें यह सोचने का अवसर देता है कि तकनीकी विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को कितना सरल बनाया है और आने वाले भविष्य में इसकी भूमिका कितनी व्यापक होने वाली है। तकनीकी विज्ञान का सबसे प्रत्यक्ष योगदान हमारे दैनिक जीवन की सुविधाओं में दिखाई देता है। सुबह उठते ही मोबाइल फोन के अलार्म से दिन की शुरुआत होती है। ऑनलाइन बैंकिंग से लेन-देन कुछ सेकंड में हो जाता है। डिजिटल भुगतान प्रणाली, विशेषकर भारत में विकसित यूपीआई प्लेटफॉर्म ने नकदी पर निर्भरता कम कर दी है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की है। सर्वेक्षण में शामिल प्रतिभागियों में यूपीआई सबसे पसंदीदा लेन-देन माध्यम बनकर उभरा है। 57 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा कि वे लेन-देन में यूपीआई का उपयोग करते हैं। वहीं, रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर अस्पताल की अपॉइंटमेंट तक सब कुछ ऑनलाइन सम्भव हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास, वर्चुअल लर्निंग और डिजिटल पुस्तकालयों ने ज्ञान को सार्वभौमिक बनाया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी विज्ञान का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक डायग्नोस्टिक मशीनें, रोबोटिक सर्जरी और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड ने चिकित्सा सेवाओं को अधिक सटीक और सुलभ बनाया है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना और डिजिटल हेल्थ मिशन तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को आम नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने देशभर में 79.91 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स बनाकर एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है।

इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक, सटीक सिंचाई प्रणाली और जैव-प्रौद्योगिकी ने उत्पादन क्षमता बढ़ाई है। उद्योगों में ऑटोमेशन और रोबोटिक्स ने उत्पादन को तेज और गुणवत्तापूर्ण बनाया है। कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग कीटनाशक, उर्वरक और उन्नत बीज का उपयोग जैसे कृषि सम्बंधी विभिन्न पहलुओं में किया जा रहा है। भारत सरकार ने तकनीकी विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में

स्वीकार किया है। डिजिटल इंडिया अभियान ने सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया है। मेक इन इंडिया ने विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलें इस क्षेत्र में बड़े बदलाव लेकर आई हैं, जिनका उद्देश्य देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

भविष्य में तकनीकी विज्ञान की उपयोगिता और भी बढ़ेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5जी और क्वांटम कम्प्यूटिंग जैसी तकनीकें उद्योग, रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगी। स्मार्ट सिटी परियोजनाएं शहरी जीवन को अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाएंगी। जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भी वैज्ञानिक अनुसंधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वही, भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां बताती हैं कि तकनीकी विज्ञान में निरंतर विकास मानव जीवन की सुगमता के साथ-साथ राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है।

अब तकनीकी विकास की बात की जा रही है तो यहां भारत की मेजबानी में आयोजित की जा रही इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। इस समागम में 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के अलावा 500 से ज्यादा ग्लोबल एआई लीडर्स ने भाग लेकर मानवता के विकास के लिए एआई की भूमिका का खाका तैयार किया है। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला प्रमुख वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन है, जो समावेशी और विकास-केंद्रित एआई में भारत की नेतृत्व भूमिका को प्रदर्शित करता है। यह समिट भारतीय मूल्यों पर आधारित है, विशेष रूप से सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के आदर्श पर। वास्तव में यह समिट इसलिए अहम है क्योंकि अब एआई सिर्फ ऐप्स तक सीमित नहीं रहा। स्वास्थ्य, खेती, शिक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी इसका असर दिख रहा है। सम्मेलन में एआई के आर्थिक असर से लेकर नियम और नवाचार के बीच संतुलन कैसे बने, इस पर भी विचार किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा का विश्लेषण कर भविष्यवाणी करने, निर्णय लेने और जटिल समस्याओं का समाधान सुझाने में सक्षम है।

तकनीकी विकास के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, रोजगार के स्वरूप में बदलाव और डिजिटल विभाजन जैसे प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं। एआई और ऑटोमेशन कुछ पारम्परिक नौकरियों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन साथ ही नए कौशल और नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम तकनीक को अपनाने के साथ-साथ मानव मूल्यों और नैतिकता को भी प्राथमिकता दें। विज्ञान का उद्देश्य केवल मशीन बनाना नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाना है। तकनीकी विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल, तेज और अधिक जुड़ा हुआ बना दिया है। भविष्य में इसकी उपयोगिता और भी व्यापक होगी, विशेषकर एआई के माध्यम से। यदि हम अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास पर निरंतर ध्यान दें तो भारत न केवल तकनीकी उपभोक्ता बल्कि तकनीकी नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकता है।

●●●

टी-20 विश्व कप में सुपर 8 तक की यात्रा

टी-20 विश्व कप क्रिकेट के इस दौर में कठिन चुनौतियों के कारण क्रिकेट प्रेमियों को सर्वश्रेष्ठ मैच देखने को मिलेंगे। दर्शक भी सुपर 8 के रोमांच का अनुभव करने के लिए आगामी 8 मार्च को विश्व विजेता के सर पर ताज देखने के लिए लालायित हैं।

9 फरवरी से शुरु हुए टी-20 विश्व कप के लीग के सभी 40 मैच समाप्त हो चुके हैं। अंतिम महत्वपूर्ण चरण (14 फरवरी से 19 फरवरी) में 18 मैच खेले गए। इन मैचों के परिणाम के बाद 8 सर्वश्रेष्ठ टीमों ने सुपर 8 में अपना स्थान पक्का किया। अधिकांश क्रिकेट प्रेमियों की दृष्टि कुछ विशेष मैचों यथा दक्षिण-अफ्रीका बनाम न्युजीलैंड, मेजबान भारत बनाम पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया बनाम मेजबान श्रीलंका तथा मेजबान श्रीलंका बनाम जिंबाब्वे के मैचों पर लगी थीं। दक्षिण अफ्रिका ने न्यूजीलैंड पर 7 विकेटों से लगभग एकतरफा जीत दर्ज की। श्रीलंका ने आस्ट्रेलिया जैसी शक्तिशाली टीम के विरुद्ध जबर्दस्त प्रदर्शन करते हुए 8 विकेटों से जीत दर्ज करते हुए विश्व कप के दावे की ओर अपने कदम आगे बढ़ा दिए। फिर भी यदि यह कहा जाए कि क्रिकेट प्रेमियों की दृष्टि सबसे ज्यादा भारत बनाम पाकिस्तान के मैच पर थी तो यह गलत नहीं होगा। कई नाटकीय राजनीतिक और कूटनीतिक उतार-चढ़ाव के बाद झक मारकर 'हां और ना के मानसिक असमंजस से ग्रस्त पाकिस्तान की टीम मैच खेलने को तैयार हुई। भारत को तो यह मैच खेलने से किसी भी प्रकार का परित्याग कभी था ही नहीं। कप्तान (सूर्याकुमार यादव) साहब कह चुके थे कि उनकी टीम की फ्लाईट की टिकटें बुक हैं। सारे खिलाड़ी तैयार हैं। पाकिस्तान की टीम न भी आए तो श्रीलंका के प्रेमदासा सटेडियम में वो टॉस के लिए अवश्य उतरेंगे।

अस्तु, एक बार मैच होना तय हुआ तो यह भी निश्चित हो गया कि एक बार फिर से वही तनावपूर्ण वातावरण दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के बीच स्टेडियम में भी स्वत: बन जाएगा। अपने-अपने देश सहित पूरी दुनिया में बसे हुए भारतीयों और पाकिस्तानियों की दृष्टि एक बार फिर से इस मैच पर टिक गई। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम की वापसी विशेष थी। साथ ही उनके एक नए स्पिनर उस्मान तारीक जिनके बॉलिंग एक्शन की जबर्दस्त चर्चा हो रही थी। दूसरी ओर भारतीय टीम पाकिस्तान के विरुद्ध अपने मैच जीतने के रेकार्ड के आधार पर आत्मविश्वास से भरी हुई थी। सूर्या कुमार ने साफ कह दिया था कि पाकिस्तान उनके मुकाबले की टीम है ही नहीं। इशान किशन की शानदार बल्लेबाजी की बल पर मैच का परिणाम भारत की अपेक्षा के अनूरूप आया। पाकिस्तान की 61 रनों से शर्मनाक हार हुई। यह और बात है कि इस बार भी न दिल मिले और न हाथ मिलाने की परम्परा शुरु हुई। रोहित शर्मा और वसीम अकरम के बीच अवश्य मित्रतापूर्ण व्यवहार देखने को मिला। दोनों एक साथ ट्रॉफी लेकर मैदान पर आए। अन्य मैचों की बात की जाए तो न्यूजीलैंड-दक्षिण अफ्रिका, बीच, आस्ट्रेलिया-श्रीलंका और श्रीलंका-जिंबाब्वे के बीच खेले जानेवाले मैचों पर सबकी दृष्टि थी। आस्ट्रेलिया जैसी शक्तिशाली टीम को हार मिली और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। यही हाल अफगानिस्तान का रहा। अच्छा खेल दिखाने के बाद भी वो भी प्रतियोगिता से बाहर हो गई।

राजीव रोहित

सुपर 8 में पहुंचनेवाली टीमों में भारत, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जिंबाब्वे, दक्षिण अफ्रिका की टीमें हैं। अन्य एशोसियेट देशों की टीमों को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि उनकी अनुभवहीनता उनकी अंतिम यात्रा को कहां समाप्त करनेवाली है? अपने सराहनीय प्रदर्शन के बाद भी उन्हें अपने बाहर होने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ होगा, लेकिन विश्व

भर के क्रिकेट प्रेमियों ने देखा कि किस तरह अमेरिका, नेपाल, नामीबिया, संयुक्त अरब अमिरात, स्कॉटलैंड, ओमान, नेपाल, और इटली जैसी टीमों ने अपने संघर्ष का अतुलनीय उत्साह दिखाया। कुछ उलटफेर तो होते-होते बचे। इंग्लैंड की नेपाल पर केवल 4 रनों से जीत यह बताने के लिए काफी है कि नेपाल ने इंग्लैंड जैसी अंतरराष्ट्रीय टीम की हालत पतली कर दी थी। अमेरिका का प्रदर्शन देखिए तो उनके गेंदबाजों ने भारत की आधी टीम को आउट कर दिया था और टीम के 100 रन भी नहीं बने थे। यह साफ था कि उन्होंने पूर्व विश्व विजेता भारतीय टीम के खेमे में हलचल मचा दी थी। सही समय पर कप्तान सूर्या कुमार यादव का बल्ला जबर्दस्त चला अन्यथा अमेरिका ने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिल की धड़कने निश्चित रूप से बढ़ा दी थीं। इन सारे मैचों के बीच सबकी दृष्टि भारत-पाकिस्तान और आस्ट्रेलिया-श्रीलंका के बीच खेले जानेवाले मैचों पर लगी थी। कहना न होगा कि आनेवाले सुपर 8 के 12 मैचों को खेलनेवाली टीमें अपनी-अपनी जीत के लिए जी जान लगा देंगी। प्रत्येक टीम 3 मैच खेलेगी। सुपर 8 के मैचों की शुरुआत 21 फरवरी से पाकिस्तान और न्युजीलैंड के बीच खेले जानेवाले मैच से होगी। दोनों टीमें शक्तिशाली हैं। एक शानदार मैच को होना तय है। भारत का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका जैसी शक्तिशाली टीम से होगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम पिछली विश्व कप की फाईनल में हुई अपनी हार का प्रतिशोध लेने के लिए आतुर होगी। भारतीय टीम अपनी जीत की लय नहीं खोना चाहेगी। दोनों टीमों ने प्रतियोगिता में शानदार खेल दिखाया है। यह तय है कि दोनों के बीच घनघोर टक्कर देखने को मिलेगी। भारत का दूसरा मैच जिंबाब्वे से है। जिंबाब्वे को कम आंकना आस्ट्रेलिया और श्रीलंका को भारी पड़ा है। इसलिए भारत को भी सचेत और सतर्क रहना होगा। भारत का अंतिम मैच वेस्ट इंडीज से है। वेस्ट इंडीज अपनी खाई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए पिछले दो दशकों से संघर्ष कर रही है। भारत को उसे भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे भी क्रिकेट में कब परिणाम किसी टीम की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दे, यह कहना कठिन होता है। भारत के लिए बाकी सभी खिलाड़ी तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोहरा रहे हैं, पर अभिषेक शर्मा जैसे स्टार बल्लेबाज का लगातार शून्य पर आउट होना अवश्य चिंता का विषय है। अन्य टीमों में इंग्लैंड को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी टीमें को हराना होगा। जिंबाब्वे के लिए भी भारत के अलावा दक्षिण अफ्रिका और वेस्ट इंडीज को हराना ही होगा। यह उनके लिए कठिन तो होगा पर वो प्रतिद्वंदियों को चौंका भी सकते हैं। सारांश यह कि सभी टीमों को अंतिम 4 में जगह पाने के लिए कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

●●●

Emerald
Crafting Imagination Into Realty
A VINOD AGARWAL ENTERPRISE
Where Everyday Life
MEETS BIGGER DREAMS
RERA NO: P-IND-23-4209
GARDENIA
by Emerald Select
PREMIUM RESIDENTIAL PLOTS
PLOTS SIZES: 1200-1800 SQ FT
KIDS PLAY AREA
EVENT STAGE
JOGGING TRACK
BADMINTON COURT
GAZEBO
MAYAKHEDI, AB BYPASS, INDORE, MP
SCAN TO SEE LUXURY IN MOTION
RERA NO: P-IND-25-5906
PARADISE COVE
by Emerald Select
PREMIUM RESIDENTIAL PLOTS
PLOTS SIZES: 4000-12000 SQ FT
Kids Play Area
Amphi theatre
Water Body
Badminton Court
Green Maze
Green Mounds
Gazebo
VILLAGE PANOD, INDORE (M.P.)
SCAN TO SEE LUXURY IN MOTION
RERA NO: P-IND-25-5789
CRESCENT
Live the precious
by Emerald Select
PREMIUM RESIDENTIAL PLOTS
PLOT SIZES: 1500-2400 SQ FT
ECO GYM
CRICKET PITCH
CLUB HOUSE ACCESS
GAZEBO
TENNIS COURT
OPEN SITTING AREA
MAYAKHEDI, AB BYPASS, INDORE, MP
SCAN TO SEE LUXURY IN MOTION
Emerald
CRESCENT
RERA NO. P-IND-25-5764
Emerald
WORLD PARK
LUXURY OFFICES
STARTING FROM 1100 SQ.FT
MAYAKHEDI, AB BYPASS, INDORE, MP
OFFICE SPACES
HIGH STREET RETAIL PLACES
CENTRAL ATRIUM
AMPHITHEATRE
SCAN TO SEE LUXURY IN MOTION
contact@emeralddevelopers.com
www.emeralddevelopers.com
AGARWAL HOUSE, 5, YASHWANT COLONY, INDORE - 452003 | +91-76106-76106

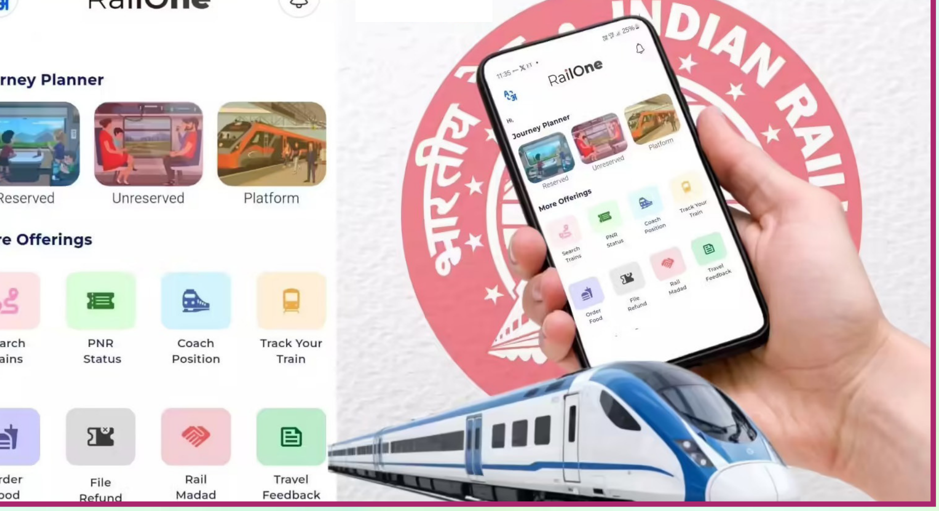

सुविधा

योगेश कुमार गोयल

वन ऐप, ऑल सर्विसेज की ओर भारतीय रेल

भारतीय रेल द्वारा संचालित 'रेलवन' एप के माध्यम से यात्रियों को अब रिजर्व टिकट, जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट, सीजन पास, पीएनआर स्टेटस, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग और कोच पोजिशन जैसी आवश्यक सुविधाएं सहज उपलब्ध होंगी।

भारतीय रेल को भारत की जीवनरेखा कहा जाता है। प्रतिदिन करोड़ों यात्री रेलमार्ग से यात्रा करते हैं। इतने विशाल नेटवर्क को सुचारु रूप से संचालित करना केवल पटरियों और इंजनों का काम नहीं बल्कि एक मजबूत डिजिटल ढांचे की भी आवश्यकता है। इसी डिजिटल परिवर्तन की कड़ी में भारतीय रेल ने लगभग एक दशक तक यात्रियों की सेवा करने वाले यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप को 1 मार्च 2026 से बंद कर उसकी जगह 'रेलवन' सुपर ऐप को प्राथमिक मंच बनाने का निर्णय लिया है।

'रेलवन' को 'वन ऐप, ऑल सर्विसेज' की दूरदर्शी अवधारणा पर विकसित किया गया है, जहां रेल यात्रा से जुड़ी हर आवश्यकता एक ही डिजिटल छत के नीचे समाहित है। अब यात्रियों को आरक्षित और अनारक्षित टिकट के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर भटकने की आवश्यकता नहीं। इस सुपर ऐप के माध्यम से रिजर्व टिकट, जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट, सीजन पास, पीएनआर स्टेटस, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग और कोच पोजिशन जैसी आवश्यक सुविधाएं सहज उपलब्ध होंगी। यही नहीं 'ई-कैटरिंग' से सीट पर भोजन, 'रेल मदद' के जरिए त्वरित शिकायत समाधान और 'आर-वॉलेट' सहित सुरक्षित डिजिटल भुगतान इसे और सशक्त बनाते हैं। 'रेलवन' केवल टिकटिंग टूल नहीं बल्कि आधुनिक, स्मार्ट और समग्र यात्रा प्रबंधन का विश्वसनीय डिजिटल साथी है।

'रेलवन' से टिकट बुकिंग सहज डिजिटल अनुभव में बदल जाएगी। अनारक्षित टिकट के लिए उपयोगकर्ता 'बुक टिकट' पर टैप कर स्टेशन और श्रेणी चुनते ही यूपीआई, कार्ड, नेटबैंकिंग या आर-वॉलेट से भुगतान कर सकते हैं और तुरंत क्यूआर कोड सहित ई-टिकट प्राप्त कर सकते हैं। आरक्षित यात्रा के लिए 'प्लान माय जर्नी' विकल्प में ट्रेन, तिथि, कोटा और क्लास चुनकर यात्री विवरण भरते ही टिकट कंफर्म हो जाता है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और समय-बचत करने वाली है। बुकिंग के बाद 'माय बुकिंग' सेक्शन से रद्दीकरण, स्थिति जांच और टिकट प्रबंधन एक क्लिक में सम्भव है यानी यात्रा अब सचमुच आपकी उंगलियों पर हैं।

3 प्रतिशत डिजिटल छूट: स्मार्ट यात्रियों के लिए अतिरिक्त लाभ

'रेलवन' ऐप के माध्यम से जनरल टिकट बुक करने वाले यात्रियों को डिजिटल भुगतान पर 3 प्रतिशत तक की आकर्षक छूट दी जा रही है। यह विशेष ऑफर 14 जुलाई 2026 तक मान्य रहेगा। रेलवे का यह कदम कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने और डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह छूट भले ही छोटी लगे, लेकिन लम्बे समय में यह उल्लेखनीय बचत में बदल सकती है। सुरक्षित, तेज और पारदर्शी भुगतान के साथ अब यात्रा और भी किफायती हो गई है।

फूड क्वालिटी सुधार: 'रेलवन' की एक महत्वपूर्ण विशेषता 'ई-कैटरिंग' सुविधा है। यात्री अपनी सीट पर ही भोजन ऑर्डर कर सकते हैं। 'रेलवन' की ई-कैटरिंग सुविधा ने रेल यात्रा के खानपान अनुभव को एक नई गुणवत्ता प्रदान की है। अब यात्री अपनी सीट पर बैठकर ही शाकाहारी, जैन एवं विविध व्यंजनों में से चयन कर सकते हैं। प्रतिष्ठित और प्रमाणित फूड पार्टनर्स के साथ जुड़ाव से भोजन की स्वच्छता और मानक सुनिश्चित किए गए हैं। ऑर्डर ट्रैकिंग की सुविधा से यात्री अपने भोजन की स्थिति पर ध्यान रख सकते हैं, जबकि डिजिटल भुगतान और आर-वॉलेट रिफंड विकल्प प्रक्रिया को पारदर्शी और सहज बनाते हैं। सबसे उल्लेखनीय पहल यह है कि यदि भोजन की गुणवत्ता या सेवा में कोई कमी हो तो यात्री तुरंत 'रेल मदद' के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे त्वरित समाधान और जवाबदेही सुनिश्चित होती है और रेल यात्रा अब स्वाद और विश्वास दोनों में बेहतर होगी। इस प्रकार फूड क्वालिटी में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम है।

स्मार्ट यात्रा की नई परिभाषा

'रेलवन' ऐप यात्रियों को रीयल-टाइम सूचना का सशक्त माध्यम प्रदान करता है। अब लाइव ट्रेन स्टेटस, पीएनआर स्थिति, कोच पोजिशन और प्लेटफॉर्म नम्बर की जानकारी एक ही डिजिटल डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। यात्री ट्रेन की वर्तमान लोकेशन देख सकते हैं, सम्भावित देरी का पूर्वानुमान पा सकते हैं और अपने कोच की सटीक स्थिति जानकर अनावश्यक भागदौड़ से बच सकते हैं।

'रेलवन' ऐप ने शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बना दिया है। रेल मदद से एकीकृत यह प्रणाली सफाई, सुरक्षा, भोजन, स्टाफ व्यवहार या अन्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतों को तुरंत ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा देती है, जिससे त्वरित कार्रवाई सम्भव होती है। इसके साथ ही कुली बुकिंग और लास्ट-माइल टैक्सी जैसी सुविधाएं यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाती हैं। बहुभाषीय समर्थन (हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में) इसे देशभर के यात्रियों के लिए सहज और समावेशी डिजिटल साथी बनाता है।

सुरक्षित भुगतान और हेल्पडेस्क सुविधा

'रेलवन' एंड-टू-एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ विकसित किया गया है, जिससे प्रत्येक लेन-देन सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड रहता है। यात्री यूपीआई, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेटबैंकिंग तथा आर-वॉलेट के माध्यम से तेज और विश्वसनीय भुगतान कर सकते हैं।

●●●

बच्चों का मन कोरे कागज की तरह होता है जो लिखेंगे वही बालमन पढ़ेगा। बच्चों में नैतिक विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें धर्म व आस्था से जोड़ा जाए। एनिमेटेड सीरियल, फिल्म व कहानी के माध्यम से उन्हें पौराणिक कथाएं, रामायण आदि की जानकारी दी जा सकती है।

कंटेंट

छोटे बच्चों को धर्म व आस्था से जोड़े

लगातार बदलती दुनिया में आज जहां एक ओर मानव समुदाय लगातार आर्थिक एवं भौतिक उन्नति के पथ पर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का पतन, मानसिक तनाव सम्बंधी समस्याएं, नशे की प्रवृत्ति और अपराधीकरण भी बढ़ रहा है। भारतीय समाज भी इससे अछूता नहीं रहा है। समाज एवं परिवार से टूटकर नई पीढ़ी एकाकीपन की ओर बढ़ रही है जिसका मूल कारण धार्मिक-सामाजिक मूल्यों की कमी है। इन मूल्यों की स्थापना पहले संयुक्त परिवारों में आपसी मेलजोल, दादी-नानी की कहानियों, सामुदायिक क्रियाकलापों, परम्पराओं एवं रस्मों तथा विविध धार्मिक कार्यक्रमों एवं अनुष्ठान के माध्यम से होती थी जो एक तरह से धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा को नई पीढ़ी के बच्चों के भीतर आत्मसात करने में सहायक होते थे, लेकिन आधुनिकता और शहरीकरण के कारण आज धर्म एवं आस्था से जुड़ने के माध्यम भी बदल गए हैं। आज पूरा समाज सोशल मीडिया एवं इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ऐसे में बच्चों को धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा हेतु ऐसे कंटेंट भी सोशल प्लेटफार्म्स पर ही उपलब्ध कराना आवश्यक है। इनमें पौराणिक कथाओं पर रील्स, कविताएं, गीत, डांस, एनिमेटेड विडियोज, कार्टून विडियोज, धार्मिक और नैतिक मूल्यों पर प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के भीतर धर्म-आस्था और नैतिक मूल्यों का बीजारोपण किया जा सकता है।

इस प्रकार का कंटेंट बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है क्योंकि बच्चे जो देखते हैं, वही करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान बाल मनोविज्ञान भी कहता है कि जितनी अधिक इंद्रियां सक्रिय होंगी अधिगम उतना ही अधिक होगा। अधिगम का अर्थ सीखने से है। बच्चा जब देखता भी है, सुनता भी है, कई बातों पर प्रतिक्रियास्वरूप बोलता भी है तो वह उसमें रुचि लेने लगता है और इस प्रकार वे मूल्य और शिक्षाएं उसके व्यवहार में रूपांतरण लाने लगते हैं। पुराणों की कथाएं गूढ़ धार्मिक विषयों को सरल करके व्यवहारिक जीवन के प्रसंगों के द्वारा लोगों को शिक्षित करने का कार्य करती हैं। यही कथाएं जब इन कंटेंट्स के माध्यम से बालमन तक पहुंचती है तो उन्हें नैतिक एवं चारित्रिक रूप से मजबूत बनाती हैं ताकि वे जीवन में हर कठिनाई का सामना बिना टूटे कर सकें। पौराणिक कथाओं में सार रूप में संदेश दिया गया है कि परोपकार सबसे बड़ा पुण्य और किसी को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। ये शिक्षाएं बच्चों के मन को निर्मल करके सत्यनिष्ठा के मूल्यों का विकास करती हैं। आज के समय में विभिन्न सीरियल्स, एनिमेटेड वीडियोज एवं वेब सीरीज के माध्यम से बच्चों तक आस्था और धर्म से जुड़ा कंटेंट पहुंच रहा है। यह कुछ सीमा तक उपयोगी भी है क्योंकि कथाओं के सीरियलों के माध्यम से बच्चों में ऐतिहासिक पात्रों की जानकारी और कथाओं का ज्ञान होता है। इसे और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए अभिभावकों और परिवार के सदस्यों का आचरण भी नैतिक शिक्षाओं को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। प्रसन्नचित्त वातावरण, सामुदायिक आयोजनों में बच्चों की सहभागिता एवं धार्मिक शिक्षा के केंद्र स्थापित करके उनके द्वारा समय-समय पर कैंप आयोजित करके बच्चों में आस्था और मूल्यों का विकास किया जा सकता है। बच्चों में मंदिर, तीर्थ-क्षेत्रों में नियमित जाने एवं वहां पर पूजा-पाठ, साफ-सफाई, भंडारा, साधु सेवा आदि का अभ्यास करके अहंकार का त्याग, सामाजिक एकता का भाव एवं मानव सेवा हेतु समर्पित मूल्यों का अभ्यास करके सनातन मूल्यों की ओर अग्रसर किया जा सकता है।

●●●

डॉ. हिमांशु थपलियाल

महत्व

एकादशी उपवास के स्वास्थ्य लाभ

हिंदू धर्म में एकादशी उपवास का अपना एक अलग ही महत्व है। व्रती इस दिन उपवास रखते हैं, साथ ही कई अनाजों का सेवन नहीं करते हैं। यह उपवास हमारे स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा है, इस आलेख में स्पष्ट है।

हिंदू धर्म में एकादशी के दिन उपवास करने का अपना एक अलग ही महत्व है। एकादशी यानी पूर्णिमा और अमावस्या के ग्यारहवें दिन, यह उपवास किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर हर 40 से 48 दिन में मंडल नामक चक्र से गुजरता है। इन दिनों में उपवास रखने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, यानी शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकाल कर शरीर शुद्ध होने की प्रक्रिया से गुजरता है।

एकादशी व्रत का महत्व केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी है। ज्योतिषीय रूप से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 12 डिग्री/24 घंटे की गति से घूमता है। इस 12 डिग्री की परिक्रमा को हिंदी में 'तिथि' कहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य से 180 डिग्री दूर होता है, तब पूर्णिमा होती है और जब यह सूर्य के साथ जुड़ता है, तब अमावस्या होती है। समुद्र की लहरों का गुरुत्वाकर्षण और चुम्बकीय खिंचाव इस चरण में मानव मन पर गहरा प्रभाव डालता है। हर ग्यारहवें दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के साथ त्रिमूर्ति बनाता है। ग्यारहवें (एकादशी) दिन वायुमंडलीय दबाव सबसे कम होता है। इसलिए यह व्रत रखने और शरीर को शुद्ध करने के लिए सबसे अनुकूल समय है। ग्यारहवें दिन के बाद हमारा शरीर वायुमंडलीय दबाव के सम्पर्क में आ जाता है और पाचन तंत्र में अत्यधिक असंतुलन पैदा करता है। इसीलिए एकादशी के दिन रखा जाने वाला उपवास हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। एकादशी के दिन उपवास करने से जहां शरीर के पाचन क्रिया में सुधार, वजन प्रबंधन और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा मिलता है। वहीं शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और कफ-पित्त दोष संतुलित रहते हैं।

विदित हो कि इस दिन हिंदू शास्त्रों में तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी और द्वादशी के अवसर पर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित की जाती है। यहां तक कि मटर, अनाज या किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन निषेध होता है।

●●●

साइबर धोखाधड़ी होने पर बैंक देगी मुआवजा

इन दिनों साइबर धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं। जिसके जाल में युवा, महिलाओं से लेकर बुजुर्ग भी फंस जा रहे हैं। कभी मोबाइल पर ओटीपी भेजकर, कभी शादी कार्ड के बहाने, कभी खुद को नकली बैंक या बीमा एजेंट बताकर, कभी पेंशन वगैरह रोकने का भय दिखाकर साइबर अपराधी भोले-भाले, मासूम लोगों को शिकार बनाते हैं। शिकार होने वालों में बड़ी संख्या में गरीब वर्ग के लोग शामिल होते हैं। पीड़ित लोगों के लिए एक सुकून देने वाला समाचार भी है। साइबर धोखाधड़ी के शिकार होने पर 25 हजार रुपए तक का मुआवजा अब सरकार देगी। जी हां, ये मजाक नहीं बल्कि सच्चाई है। बैंक फ्रॉड से जुड़े छोटे मामलों में ग्राहकों को 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। केंद्रीय बैंक आरबीआई इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी नियम और गाइडलाइन लाने की तैयारी कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 4 से 6 फरवरी तक चली मॉनिटरी पॉलिसी की मीटिंग के बाद विगत दिवस इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा, केंद्रीय बैंक छोटे मूल्य के धोखाधड़ी वाले लेनदेन के मामले में बैंक ग्राहकों को मुआवजा देने के लिए नए नियम तैयार कर रहा है।

●●●

47 परिवारों की हुई घर वापसी

ओडिशा के सम्बलपुर जिले के बामरा प्रखंड अंतर्गत सोलबागा गांव में 47 परिवारों के कुल 141 सदस्यों ने घर वापसी कार्यक्रम के अंतर्गत घर वापसी की। बताया जाता है कि उक्त कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया गया था। विगत दिवस वेदमाता महिला सेवा आश्रम परिसर में आयोजित पंचकुंडीय धर्मरक्षा यज्ञ के दौरान 47 परिवारों के कुल 141 सदस्यों ने घर वापसी कार्यक्रम के अंतर्गत पुनः हिंदू धर्म स्वीकार किया।

वैदिक मंत्रोच्चार, हवन और पारम्परिक अनुष्ठानों के साथ 141 सदस्यों ने घर वापसी कीं। बताया जाता है कि उक्त ये सभी परिवार पूर्व में पादरियों और मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई धर्म अपना चुके थे। वीएचपी कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार सम्पर्क, संवाद और जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद पुनः उन परिवारों ने हिंदू धर्म में लौटने का निर्णय लिया। घर वापसी करने वाले सभी परिवारों का कार्यक्रम में भव्य स्वागत किया गया। उनके चरण पखारे गए, उन्हें फूलमालाएं और हवन में आहुति दिलाई गई। वीएचपी के धर्म प्रसार विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी अच्युतानंद कर के मार्गदर्शन में कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर वीएचपी की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडली के सदस्य स्वामी जीवनमुक्तानंद पुरी, पश्चिम ओडिशा प्रांत अध्यक्ष राजकुमार बड़पांडा, संगठन मंत्री सत्यनारायण सेनापति, शेषदेव बाबा और बाबा शिवानंद सहित कई लोग उपस्थित थे।

●●●

सेवा सहयोग द्वारा सेवा फेस्ट-2026 महोत्सव का आयोजन

पुणे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉल्यूनटरिंग घोषित किए जाने पर सेवा सहयोग फांउडेशन द्वारा सेवा फेस्ट - उत्सव सेवेचा नामक भव्य सामाजिक महोत्सव का आयोजन शनिवार, 14 फरवरी 2026 को सिंहगढ़ रोड स्थित कलाग्राम में उत्साहपूर्वक किया। उक्त महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति, स्वयंसेवक, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, अधिकारी तथा नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारम्भ सेवा क्षेत्र में कार्यरत मान्यवरों के प्रेरणादाई उद्बोधनों से हुआ। इस अवसर पर विवेक कुलकर्णी (प्रेसिडेंट, गरवारे टेक्निकल कॉलेज, पुणे), विनोद जाधव (के.जे. ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे), प्रवीण कुलकर्णी (प्लांट डी. सी. हेड, इन्फोसिस), किशोर मोघे (डायरेक्टर, सेवा सहयोग फाउंडेशन) तथा विनीत कोंडेजर (एच.आर. हेड, सेवा सहयोग फाउंडेशन) उपस्थित थे। अपने सम्बोधन में प्रवीण कुलकर्णी ने स्वयंसेवकों से परिवार सहित सेवा गतिविधियों में भाग लेने का विशेष आग्रह किया।

उत्सव के दौरान किशोरी विकास जानकारी पुस्तिका, चेतना परियोजना प्रकाशन तथा महिला सशक्तिकरण दशक पूर्ति पुस्तिका का विमोचन मान्यवरों के करकमलों द्वारा किया गया।

पुणे। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी और सशस्त्र क्रांति के जनक वासुदेव बळवंत फडके की 142वें पुण्यतिथि के अवसर पर संगमवाड़ी पुल के पास स्थित उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उक्त अवसर पर योगशिक्षक सुभाष बाळकृष्ण फडके, दत्तात्रय लक्ष्मण फडके, चंद्रकांत प्रभाकर फडके, चंद्रकांत दत्तात्रय फडके, दिगम्बर गोपाळ फडके, सुलभा लिमये, नंदकिशोर फडके आदि उपस्थित थे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देवगिरी प्रांत सेवा भारती सहसचिव तथा पूर्णवादी नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष तथा बालरोग विशेषज्ञ डॉ. सुभाष जोशी के जन्मदिवस के अवसर पर गोवर्धन गोशाला द्वारा उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर गोशाला के अध्यक्ष डॉ. मुरलीजी जेसवाणी, उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, गोवर्धन गोशाला के सचिव तथा बीड के हिंदी विवेक मासिक पत्रिका के प्रतिनिधि गणेश गुरखुदे, कोषाध्यक्ष आनंद मुंदडा (बार्शीकर), संचालक किशनसिंह चौहाण, सभासद प्रशांत डोरले उपस्थित थे।

आचार्य नीरज शास्त्री साहित्य सेवा सम्मान से अलंकृत

आगरा में पहला दो दिवसीय विराट साहित्योत्सव धरा चेतना फाउंडेशन द्वारा 'ब्रजधरा-साहित्योत्सव' का विगत दिवस आयोजन किया गया। इस उत्सव में चिकित्सा, अर्थशास्त्र, अभिनय, संगीत, विद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा, कला तथा लेखन से जुड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सुविख्यात विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों में मथुरा के राष्ट्रवादी साहित्यकार आचार्य नीरज शास्त्री को सम्मानित किया गया। इन्हें साहित्य सेवा सम्मान प्रदान किया गया। सभी उपस्थित साहित्यकारों को भारतीय संस्कृति विभाग के विशिष्ट प्रतिनिधि पद्मश्री बलवंत सिंह ठाकुर, धरा चेतना फाउंडेशन की अध्यक्ष दीपाली सिंह, सचिव अक्षय सिंह एवं आयोजन के सूत्रधार एवं सफल संचालक गीतकार कुमार ललित द्वारा शॉल, दुपट्टा व सम्मान पत्र प्रदान कर अलंकृत किया गया।

TJSB SAHAKARI BANK LTD.
MULTI-STATE SCHEDULED BANK
Bharose ka Bank Bhavishya ka Bank
CRAFT YOUR GROWTH STORY WITH TJSB'S
SME LOAN
Avail loan at an attractive rate of interest
Quick Processing
Non-fund based facilities like LC/BG
Repayment period of 84 months*
All MSME in manufacturing, trading and service sector
Fund-based facilities like Term loans, Working capital
*T&C Apply
www.tjsb.bank.in | : - 022-48897204